बुधवार, 8 जुलाई, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

एमबाप्पे ने मारिला की नस्लवादी टिप्पणियों कीकड़ी आलोचना की

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

सतलुज हर घर तक पहुँच गई,अब नहीं रुकेगी

Page-05

ईरान को ट्रंप की सख्त चेतावनी, शांति वार्ता के बीच बढ़ा पश्चिम एशिया का तनाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की प्राथमिकता शांतिपूर्ण समाधान है, लेकिन यदि परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो उसके पास हर विकल्प मौजूद है।ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और संभावित युद्धविराम को लेकर विभिन्न स्तरों पर कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रतिबंधों को लेकर लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी तेज हुई है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंकाएं बढ़ गई हैं।अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका प्रशासन संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और सहयोगी देशों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूसरी ओर ईरान की ओर से अब तक ट्रंप के ताजा बयान पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील कर रहा है।

राम मंदिर ट्रस्ट के खर्चों की SIT जांच तेज,

प्राण प्रतिष्ठा समेत 124 करोड़ रुपये के व्यय का ऑडिट

अयोध्या स्थित राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न धार्मिक और प्रशासनिक आयोजनों पर हुए खर्चों की जांच अब और व्यापक हो गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने ट्रस्ट द्वारा 124 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के उपयोग से संबंधित दस्तावेजों, भुगतान प्रक्रियाओं और वित्तीय रिकॉर्ड की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। जांच के दायरे में जनवरी 2024 में आयोजित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, वर्ष 2025 के महाकुंभ से जुड़ी व्यवस्थाएं तथा नवंबर 2025 में आयोजित ध्वजारोहण समारोह सहित कई बड़े कार्यक्रम शामिल हैं। इन आयोजनों पर हुए खर्च और उनकी स्वीकृति प्रक्रिया की गहन समीक्षा की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, यह जांच किसी एक शिकायत के आधार पर नहीं, बल्कि एक व्यापक वित्तीय ऑडिट का हिस्सा है। जांच एजेंसियां यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि ट्रस्ट द्वारा किए गए सभी व्यय निर्धारित नियमों, प्रशासनिक मंजूरियों और वित्तीय प्रक्रियाओं के अनुरूप हुए हैं या नहीं। इसके लिए SIT भुगतान संबंधी फाइलों, निविदाओं, ठेकों, स्वीकृति पत्रों, लेखा अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों का मिलान कर रही है। जिन एजेंसियों और कंपनियों को कार्य आवंटित किए गए थे, उनसे संबंधित रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में शामिल किए जा रहे हैं।जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार या धन के दुरुपयोग की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच का उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं से प्राप्त दान और सार्वजनिक धन का उपयोग पूरी पारदर्शिता तथा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया गया है। यदि जांच के दौरान किसी स्तर पर प्रक्रिया संबंधी कमी, नियमों के उल्लंघन या वित्तीय अनियमितता के संकेत मिलते हैं, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।राम मंदिर देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए इस जांच पर राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर विशेष नजर बनी हुई है। इतने बड़े धार्मिक प्रकल्पों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे और भविष्य में भी ऐसे परियोजनाओं के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट या SIT की ओर से जांच के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष या आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। जांच प्रक्रिया जारी है और उसके पूरा होने के बाद ही किसी भी प्रकार की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

शेख हसीना विरोधी कार्यक्रम में मची अफरा-तफरी

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के निकट सावर क्षेत्र में आयोजित नेशनल सिटिज़न पार्टी (NCP) की राजनीतिक रैली के दौरान हुए विस्फोट ने देश की राजनीतिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रैली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के दौरान अचानक हुए धमाके से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गईस्थानीय अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट में कम से कम तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया तथा बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को जांच के लिए मौके पर बुलाया गया। अधिकारियों ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्र किए हैं।धमाके के कारणों का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि यह हमला किसी संगठित साजिश का हिस्सा था या किसी स्थानीय समूह की कार्रवाई। सुरक्षा बल आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के महीनों में बांग्लादेश की राजनीति में बढ़ते तनाव के बीच इस तरह की घटना सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है।

महाराष्ट्र में बारिश का कहर, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद और हादसों में छह लोगों की मौत

महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। राजधानी मुंबई सहित कई जिलों में तेज बारिश, जलभराव और तेज हवाओं के कारण सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है। लगातार बारिश को देखते हुए मुंबई प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी सरकारी, निजी और बीएमसी संचालित स्कूलों तथा कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। लोकल ट्रेन और बस सेवाओं पर भी बारिश का असर देखा गया, जबकि कई स्थानों पर पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और दीवार गिरने जैसी घटनाओं में अब तक छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। राहत एवं बचाव दल लगातार प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को अगले आदेश तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है।पुणे, रायगढ़, ठाणे और पालघर समेत कई जिलों में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। नदियों और जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटे तक कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रह सकती है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने, आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जनता से मौसम विभाग की सलाह का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है।

भूपेंद्र यादव के कार्यालय से तीन वरिष्ठ अधिकारियों की विदाई

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय में एक साथ तीन वरिष्ठ अधिकारियों को हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलावों की चर्चा तेज हो गई है। सरकार द्वारा 3 जुलाई को जारी अलग-अलग आदेशों में मंत्री के निजी सचिव (PS) और दो अतिरिक्त निजी सचिवों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। इनमें से कुछ अधिकारियों को उनके मूल कैडर में वापस भेजा गया है, जबकि अन्य की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है।एक साथ तीन वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला या हटाया जाना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से अलग माना जा रहा है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इसे संभावित कैबिनेट विस्तार या फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से इस कदम के पीछे किसी विशेष कारण की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। रिपोर्टों के अनुसार, मंत्रालय में प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया भी चल रही है। कई बार मंत्रालयों में कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाता है।

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामला

गुजरात हाई कोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी

वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों को दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए 11 अन्य दोषियों की उम्रकैद की सजा भी कायम रखी। इसके साथ ही अदालत ने विस्फोट में जान गंवाने वाले 56 लोगों के परिजनों और घायल पीड़ितों को मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इन धमाकों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लंबी जांच और सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने वर्ष 2022 में 38 दोषियों को फांसी तथा 11

अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।गुजरात हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा के बाद विशेष अदालत के निर्णय को बरकरार रखा। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मृतकों के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तथा घायलों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला देश के सबसे चर्चित आतंकवादी मामलों में से एक में महत्वपूर्ण माना जाएगा। हालांकि दोषियों के पास अब भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील का विकल्प उपलब्ध है। दूसरी ओर पीड़ित परिवारों ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

सीरिया में फिर दहशत

दमिश्क धमाकों से दहला राजधानी का मध्य क्षेत्र

यह घटना दमिश्क में 'जस्टिस पैलेस' के पास एक कैफे में हुए विस्फोटक धमाके के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हो गए थे।

सीरिया के दमिश्क में मंगलवार को कई धमाके हुए। ठीक उसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति सीरिया के राष्ट्रपति से एक अहम दौरे पर मुलाकात कर रहे थे। इमैनुएल मैक्रों सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शारा से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए ही थे कि तभी 'फोर सीजन्स होटल' के पास धमाके हुए। सीरियाई अधिकारियों ने इस घटना पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। सीरियाई मीडिया ने बताया कि मैक्रों 'फोर सीजन्स' में ही ठहरे हुए थे। सरकारी मीडिया ने एक अज्ञात सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि राजधानी के बीचों-बीच हुए ये दो धमाके विस्फोटक उपकरणों से किए गए थे। घटनास्थल से धुएं का गुबार उठता देखा जा सकता था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फुटेज में एक गाड़ी जलती हुई और सड़क पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। फ्रांस का कहना है कि इमैनुएल मैक्रों सुरक्षित हैं। हताहतों की संख्या के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिली है और किसी भी गुट ने तुरंत इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। दरअसल, अल-शारा के सत्ता में आने के बाद से सीरिया का दौरा करने वाले मैक्रों पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। उनका यह दौरा अंकारा, तुर्किये में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में जाने से पहले हो रहा है। मैक्रों ने यूरोप और अमेरिका को सीरिया पर लगे ज़्यादातर प्रतिबंध हटाने के लिए मनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वे सोमवार रात एक आर्थिक प्रतिनिधिमंडल के साथ देश पहुंचे थे। उनका अपने समकक्ष के साथ समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर करने का कार्यक्रम है, क्योंकि 14 साल के युद्ध के बाद यह जर्जर देश पुनर्निर्माण में मदद के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। सरकारी मीडिया ने एक अज्ञात सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि राजधानी के बीचों-बीच हुए दो धमाके विस्फोटक उपकरणों की वजह से हुए। घटनास्थल से धुएं का गुबार उठता देखा जा सकता था। यह इलाका दमिश्क की एक व्यस्त सड़क पर है और पर्यटन मंत्रालय तथा दमिश्क राष्ट्रीय संग्रहालय के मुख्यालय के पास है। यह घटना दमिश्क में 'जस्टिस पैलेस' के पास एक कैफे में हुए विस्फोटक धमाके के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हो गए थे। बता दें कि सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल किसी भी समूह ने तुरंत इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बल तुरंत कैफे पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर दी। वे इस हमले की जांच कर रहे हैं। दमिश्क के गवर्नर माहेर इद्लिबी ने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही अपनी प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों की घोषणा करने वाला है। इद्लिबी ने बताया कि वह उपकरण "साधारण" लग रहा था और उन्होंने संकल्प लिया कि इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो में कई घायल लोग जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे थे, और पास ही पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। बाद में एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचीं, जिन्होंने मौके पर ही लोगों का प्राथमिक उपचार किया और गंभीर रूप से घायलों को सीरिया की राजधानी के अस्पतालों में पहुंचाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जकार्ता की अपनी यात्रा के दूसरे दिन इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। यह संबोधन उन्हें राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो द्वारा इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बिंतंग आदिपूर्णा' से सम्मानित किए जाने के बाद हुआ। संसद को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने भारत के प्रति गर्मजोशी, स्नेह और सम्मान के लिए इंडोनेशिया के लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने मिले सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ अपनी गहरी दोस्ती और मजबूत कामकाजी संबंधों की सराहना करते हुए भारत-इंडोनेशिया संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए और 'लोकतंत्र की जननी' के एक गर्वित नागरिक के तौर पर, मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं... आज सुबह इंडोनेशिया के लोगों ने जो प्यार और गर्मजोशी भरा स्वागत किया, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का सौभाग्य भी मिला। मैं विनम्र और आभारी हृदय से अनगिनत भारतीयों के प्रति इंडोनेशियाई लोगों के स्नेह को स्वीकार करता हूं।प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया की संसद में कहा कि भारत का वैश्विक नज़रिया क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के बजाय समावेशी विकास पर आधारित है। उन्होंने "सबका साथ, सबका विकास" के सिद्धांत पर ज़ोर देते हुए कहा कि यह सोच सहयोग और सामूहिक भागीदारी के ज़रिए तरक्की के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 'इको-रेस्टोरेशन मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026' का शुभारंभ किया

भारी बारिश के कारण हवाई यातायात बाधित

देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। मंगलवार को दिल्ली और मुंबई में भारी बारिश के कारण हवाई यातायात बाधित हो गया, जिसके चलते एयरलाइंस ने यात्रियों को संभावित देरी के बारे में चेतावनी देते हुए यात्रा सलाह जारी की है। उनसे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ानों की स्थिति की जांच करने की अपील की है। इंडिगो एयरलाइंस ने कहा कि दिल्ली में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण उड़ान कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं और उसकी टीमें स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं। एयरलाइन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानों के कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। हम मौसम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और आपको सुरक्षित और सुचारू रूप से आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।' एयरलाइन ने यात्रियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में अपडेट रहने और बारिश के कारण धीमी गति से चल रहे यातायात के चलते हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त यात्रा समय को ध्यान में रखने की सलाह दी। इंडिगो ने कहा कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट या

ऐप के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में अपडेट रहें। साथ ही, कृपया अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय निकालें, क्योंकि धीमी गति से चलने वाले यातायात के कारण हवाई अड्डे तक सड़क यात्रा प्रभावित हो सकती है। यात्रियों को सहायता का आश्वासन देते हुए एयरलाइन ने कहा कि कृपया निश्चिंत रहें कि हमारी टीमें हर कदम पर आपकी सहायता करने और पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए यहां मौजूद हैं। आपके धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद। इसके अलावा, एयर इंडिया ने यात्रियों को यह भी चेतावनी दी कि खराब मौसम दिल्ली से आने-जाने वाली उड़ानों को प्रभावित कर सकता है। एयरलाइन ने X को जारी अपनी सलाह में कहा कि खराब मौसम की स्थिति दिल्ली से आने-जाने वाली उड़ानों के संचालन को प्रभावित कर सकती है।

विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए भारी संख्या में सैनिकों को किया तैनात

पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में जारी विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए भारी मात्रा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। यह तैनाती रावलकोट समेत उन जगहों पर ज्यादा की गई है, जहां प्रदर्शन जारी हैं। पीओके में 27 जुलाई को आम चुनाव भी होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर उससे पहले विरोध प्रदर्शनों को दबाना चाहता है। ऐसी आशंका है कि पाकिस्तानी सुरक्षाबल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बर्बरता से पेश आ सकते हैं, जैसा उन्होंने बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में किया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की सेना और दूसरे प्रशासनिक तंत्र मतदान से पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में शांतिपूर्ण माहौल बनान चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को सीधा निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आगामी चुनावी प्रक्रिया में विरोध प्रदर्शन से कोई बाधा उत्पन्न न हो। पीओके में जम्मू-कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी (JKAAC) के नेतृत्व में हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह प्रदर्शन पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों और सरकार की विफलताओं के खिलाफ है। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि वे अब बातचीत नहीं करेंगे और प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं देंगे। सूत्रों ने बताया कि सैन्य अधिकारियों ने रावलकोट में जमा प्रदर्शनकारियों को अंतिम अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें उनसे शांतिपूर्वक अपना धरना समाप्त करने या जबरन हटाए जाने की कार्रवाई का सामना करने को कहा गया है। माना जा रहा है कि सुरक्षा अधिकारियों ने अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं को चेतावनी भी दी है कि यदि वे स्वेच्छा से आंदोलन वापस लेने से इनकार करते हैं, तो सुरक्षा बल विरोध स्थल को खाली कराने के लिए अभियान शुरू कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शन को खत्म करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, तो सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर अभियान चला सकती है।

अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की सूची में एक और प्रतिष्ठित सम्मान

सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बिन्तांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचे हैं और मंगलवार उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान 'बिन्तांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने यह पदक प्रदान किया। पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने पर एक ओर जहां बधाइयां मिल रही हैं तो वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इतिहास में ऐसे इकलौते नेता के तौर पर याद किए जाएं जिन्होंने अवॉर्ड और सम्मान पाने के लिए दुनिया भर की यात्राओं में टैक्स देने वालों का हजारों करोड़ रुपया खर्च किया। इसके उलट, साम्राज्यवाद-विरोधी सोच, लोकतंत्र और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान इतना अहम था कि उनके निधन के दशकों बाद भी

उनकी विरासत का सम्मान किया पवन खेड़ा ने कहा कि जिस अवॉर्ड का जश्न आज मोदी के समर्थक मना रहे हैं, वही अवॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1995 में मरणोपरांत दिया जा चुका था। यही पुरस्कार बीजू पटनायक को भी इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में प्रदान किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि यह उनके ठोस कार्यों के लिए था, न कि लॉबिंग के माध्यम से। कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी नेता की विरासत का आकलन विदेशों में जीते गए पुरस्कारों की संख्या से नहीं होता। उसका मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि उन्होंने कैसे शासन किया। क्या न्याय, विवेक और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ शासन किया। उस कसौटी पर पीएम मोदी का प्रदर्शन शून्य है।

संपादक की कलम से

लोकसभा के मानसून सत्र से पहले तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसदों की सदस्यता को लेकर लोकसभा अध्यक्ष के सामने खड़ा सवाल केवल दो राजनीतिक दलों का आंतरिक विवाद नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र, संसदीय मर्यादाओं और दल-बदल विरोधी कानून की विश्वसनीयता की भी बड़ी परीक्षा है। आने वाला निर्णय यह तय करेगा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की निष्ठा व्यक्तिगत राजनीतिक हितों के प्रति अधिक महत्वपूर्ण है या जनता द्वारा दिए गए जनादेश के प्रति।भारत में दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अवसरवादी राजनीति से दूर रखना था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में जिस तरह बड़ी संख्या में विधायक और सांसद दल बदलते रहे हैं, उसने इस कानून की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कई मामलों में कानूनी प्रावधानों और तकनीकी व्याख्याओं का सहारा लेकर जनादेश की मूल भावना को कमजोर किया गया है।लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रभाव भविष्य की राजनीति पर पड़ेगा। यदि दल-बदल के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष निर्णय नहीं होंगे, तो राजनीतिक दलों में टूट-फूट का सिलसिला और तेज हो सकता है। दूसरी ओर, यदि कानून का कठोर और समान रूप से पालन होता है, तो राजनीतिक दलों में अनुशासन और लोकतांत्रिक जवाबदेही दोनों मजबूत होंगे।हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष का पद पूरी तरह निष्पक्ष माना जाता है। इसलिए उनका हर फैसला केवल कानूनी दृष्टि से ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता की कसौटी पर भी खरा उतरना चाहिए। किसी भी पक्ष के प्रति राजनीतिक झुकाव की आशंका लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता के विश्वास को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनने और संवैधानिक विशेषज्ञों की राय लेने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।आज आवश्यकता केवल कानून लागू करने की नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति में सुधार लाने की भी है। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि बार-बार दल बदलकर जनादेश की दिशा बदलते रहेंगे, तो मतदाताओं का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास कमजोर होगा। राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा होती हैं, जहां उनके अपने ही सांसद और विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं।लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव जीतने से नहीं, बल्कि जनादेश का सम्मान करने से सुनिश्चित होती है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष का आगामी फैसला केवल कुछ सांसदों की सदस्यता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारतीय संसदीय लोकतंत्र में दल-बदल कानून की विश्वसनीयता और राजनीतिक नैतिकता की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है।

मानसून सत्र से पहले बड़ा फैसला
बागी सांसदों की सदस्यता पर स्पीकर करेंगे निर्णय

उधर, महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) को भी बड़ा झटका लगा है। पार्टी के टिकट पर चुने गए नौ सांसदों में से छह सांसदों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की घोषणा कर दी है। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने भी इन सांसदों के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है।

लोकसभा के आगामी मानसून सत्र से पहले संसद की राजनीति में दल-बदल विरोधी कानून एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और शिवसेना (यूबीटी) में हुई बगावत के बाद दोनों दलों ने अपने बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अब इस पूरे विवाद पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हाथ में है, जिस पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं।संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसदों से जुड़े दल-बदल विरोधी कानून के मामलों पर महत्वपूर्ण फैसला सुना सकते हैं। दोनों दलों ने अपने-अपने बागी सांसदों को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार, अध्यक्ष ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और पार्टी से अलग हुए सांसदों के समूह, दोनों का पक्ष विस्तार से सुना है। इसी तरह की प्रक्रिया शिवसेना (यूबीटी) के मामले में भी अपनाई गई है।जानकारी के अनुसार, लोकसभा सचिवालय के विधि एवं संवैधानिक विशेषज्ञ इस मामले के कानूनी पहलुओं का गहन अध्ययन कर रहे हैं। विशेषज्ञों की टीम पूर्व में विभिन्न विधानसभा और लोकसभा अध्यक्षों द्वारा दिए गए फैसलों तथा दल-बदल कानून से जुड़े न्यायिक निर्णयों का भी विश्लेषण कर रही है, ताकि निर्णय पूरी तरह संवैधानिक और कानूनी रूप से मजबूत हो। इन्हीं सुझावों के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष 20 जुलाई से पहले अपना अंतिम फैसला सुना सकते हैं।टीएमसी में सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया जब 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर निर्वाचित 29 सांसदों में से 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। इन सांसदों ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) का दामन थाम लिया और लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। इतना ही नहीं, इस समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार को समर्थन देने और गठबंधन में शामिल होने की इच्छा भी जताई है। इस बीच टीएमसी के एक सांसद के निधन के कारण एक सीट फिलहाल रिक्त है।उधर, महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) को भी बड़ा झटका लगा है। पार्टी के टिकट पर चुने गए नौ सांसदों में से छह सांसदों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की घोषणा कर दी है। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने भी इन सांसदों के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है।टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) दोनों का तर्क है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार किसी भी दल के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अयोग्यता से छूट तभी मिल सकती है, जब पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सदस्य सामूहिक रूप से अलग होकर नया समूह बनाएं। दोनों दलों का दावा है कि मौजूदा परिस्थितियों में यह शर्त पूरी नहीं होती, इसलिए बागी सांसदों की सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। अब इस पूरे विवाद पर लोकसभा अध्यक्ष का फैसला न केवल संबंधित सांसदों के राजनीतिक भविष्य, बल्कि संसद के भीतर दल-बदल कानून की व्याख्या के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है।

नई अटकलों के बीच राजनीतिक हलचल फिर से तेज़

महाराष्ट्र में शरद पवार की अगुवाई वाली NCP (SP) के भविष्य को लेकर नई अटकलों के बीच राजनीतिक हलचल फिर से तेज़ हो गई है। कांग्रेस के साथ पार्टी के प्रस्तावित विलय को समर्थन न मिलने की खबरों के बाद, अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा ज़ोरों पर है कि पार्टी NDA के साथ गठबंधन पर विचार कर सकती है। हालांकि NCP (SP) ने ऐसे सभी दावों का पुरज़ोर खंडन किया है, लेकिन ये अटकलें ऐसे समय में सामने आई हैं जब विपक्षी गठबंधन 'महा विकास अघाड़ी' (MVA) को बढ़ती अंदरूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक, NCP (SP) ने कांग्रेस के सामने दो बार विलय का प्रस्ताव रखा था। गौरतलब है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले भी कांग्रेस और NCP (SP) के विलय की संभावना पर चर्चा हुई थी, लेकिन चुनाव प्रचार के कारण इसे रोक दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से इस प्रस्ताव पर चर्चा करने को कहा था। बाद में कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी महाराष्ट्र इकाई से राय मांगी, जहां ज़्यादातर राज्य नेताओं ने कथित तौर पर इस कदम का विरोध किया। नतीजतन, अब माना जा रहा है कि विलय के प्रस्ताव की गति धीमी पड़ गई है।यह झटका ऐसे समय में लगा है जब MVA पहले से ही अपनी एकता को लेकर सवालों के घेरे में है। हाल के महीनों में इस गठबंधन को कई राजनीतिक झटके लगे हैं, जिनमें शिवसेना (UBT) में हुई बगावत भी शामिल है, जहाँ छह सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। मुंबई में हाल ही में हुई MVA की बैठक में, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गठबंधन की एकता पर खुलकर सवाल उठाए और पूछा, "हम कहते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन क्या हम सच में साथ हैं? इन हालात को देखते हुए, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि NCP (SP) और झटकों से बचने और अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकती है, हालाँकि ऐसी किसी भी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।खबरों के मुताबिक, विलय की बातचीत रुकने के बाद से यह अटकलें तेज़ हो गई हैं कि NCP (SP) के कुछ सांसद और विधायक NDA का समर्थन करने या सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। ऐसी भी अपुष्ट खबरें हैं कि अगर सांसद सुप्रिया सुले और कुछ अन्य नेता NDA में शामिल होते हैं, तो उन्हें केंद्र में अहम ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं। हालाँकि, इनमें से किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। NCP (SP) नेता और विधायक रोहित पवार ने इन खबरों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कांग्रेस में विलय, NDA में शामिल होने या सत्ताधारी गठबंधन को बाहर से समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उनके अनुसार, ये महज़ राजनीतिक अफ़वाहें हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है।

मुंबई जलभराव पर आदित्य ठाकरे का BJP पर हमला

शिवसेना (UBT) के विधायक आदित्य ठाकरे ने बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में जलभराव और सड़कों की खस्ता हालत को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों से सत्ता में होने के बावजूद सरकार जलभराव और खराब सड़कों जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई। आदित्य ठाकरे ने कहा कि भाजपा (BJP) हर समस्या का दोष किसी और पर मढ़ने की कोशिश करती है, कभी पंडित नेहरू पर, तो कभी ठाकरे परिवार पर। शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने आज पत्रकारों से बात करते हुए मुंबई में जलभराव और सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर भाजपा नीत महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा हर समस्या के लिए कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कभी ठाकरे परिवार को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन अपनी जवाबदेही स्वीकार नहीं करती। पिछले चार वर्षों से शहर का प्रशासन, शहरी विकास विभाग और सरकार भाजपा के नियंत्रण में है, इसके बावजूद पहली ही बारिश में अंधेरी सबवे समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हिंदमाता, गांधी मार्केट और मिलन सबवे जैसे क्षेत्रों में हर साल जलभराव की समस्या सामने आती है। इन इलाकों से भाजपा के विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, फिर भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि चार वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद हालात नहीं बदले तो विकास कार्यों पर खर्च किया गया पैसा आखिर कहां गया। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बारिश ने मुंबई की सड़कों की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है। शहर में जगह-जगह गड्ढे हैं और हाईवे भी खराब हालत में हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में ऐसी स्थिति नहीं थी। ठाकरे ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार विकास कार्यों की बजाय भ्रष्टाचार में व्यस्त है और लगभग हर विभाग में अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। विपक्ष के आरोपों के बीच मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा, "काफी इंतजार के बाद मुंबई में बारिश आई थी। लेकिन जो कुछ घटना हुई है वो दुखद है। मेरा मन इससे व्यथित है। आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। आज उतनी बारिश नहीं है। लोगों से मैं अपील करना चाहती हूं कि सब काम चालू हैं। हर नगरसेवक (पार्षद) अपने वार्ड में घूम रहा है। प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। मैं खुद नजर बनाए हूं, विरोधी पक्ष के नेता भी थे। हम सब मुंबई के लिए काम कर रहे हैं।"

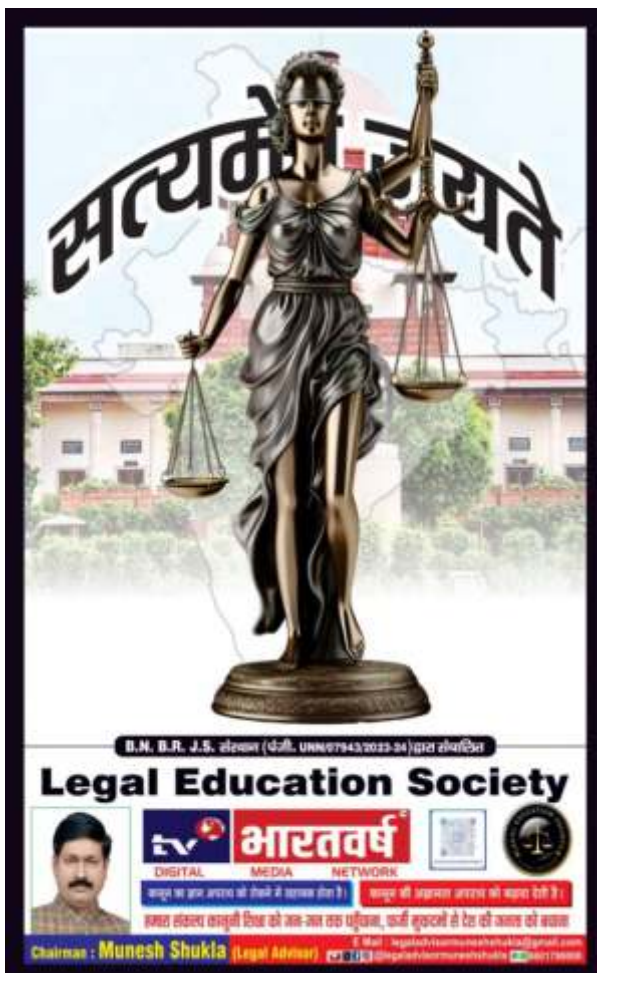

सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद बदला कंटेंट 9वीं की किताब में न्यायपालिका का नया स्वरूप

नई एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत स्कूलों के लिए नई किताबें ला रही है। कुछ महीने पहले बच्चों की किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तीखी टिप्पणी की थी। यहां तक कि ऑनलाइन और ऑफलाइन किताबें हटाई गई हैं। जो किताबें बट चुकी थीं, उन्हें वापस मंगावा गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT को लिखित में माफी मांगनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट की 'क्लास' के बाद एनसीईआरटी ने अब पूरी कहानी पलट दी है।

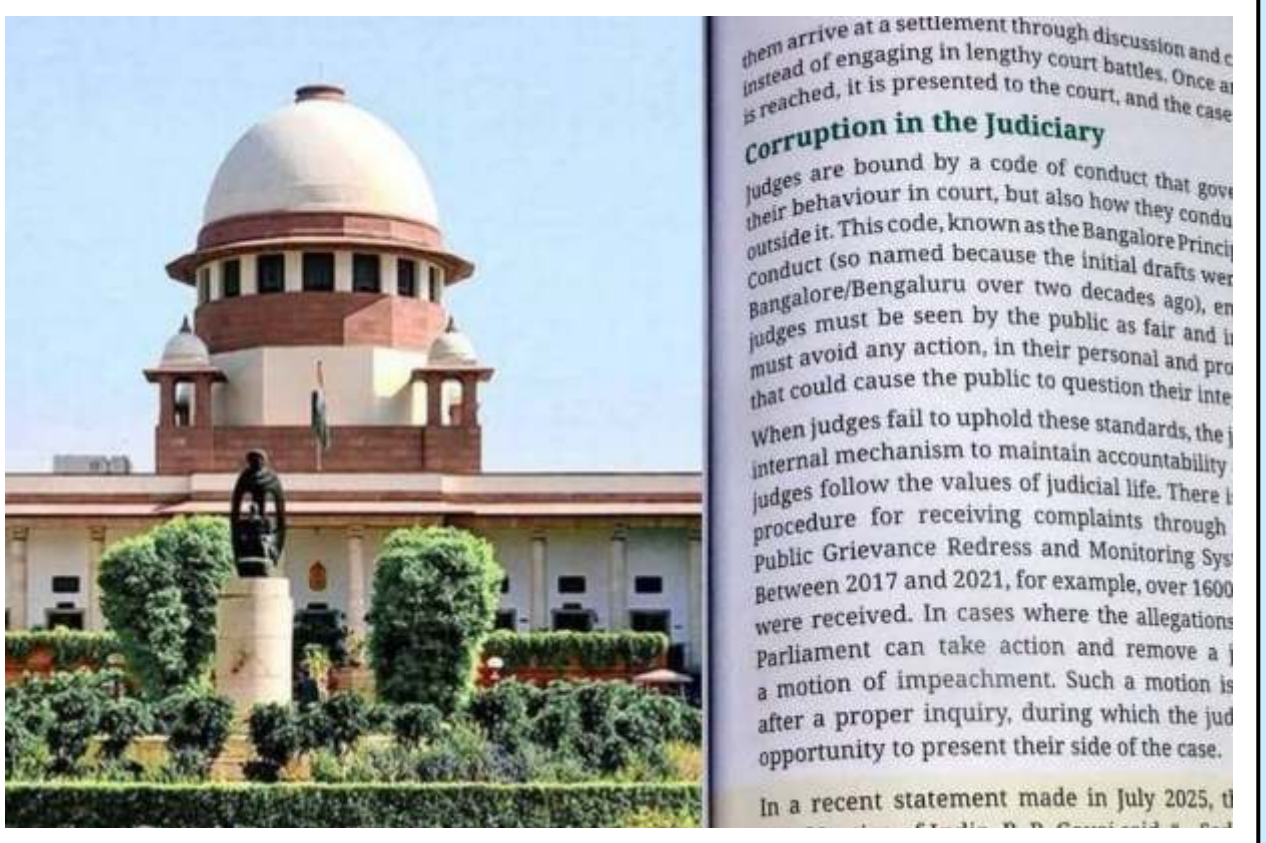

दरअसल, एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में 'ज्यूडिशरी में करप्शन' को लेकर कई चीजें छापी थीं। उस किताब के एक हिस्से में न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों - जैसे भ्रष्टाचार, केसों का ढेर लगना और लोगों का भरोसा कम होना आदि पर चर्चा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान (suo motu cognisance) लिया, चैप्टर के कुछ हिस्सों को आपत्तिजनक बताया और किताब के पब्लिकेशन, दोबारा प्रिंटिंग और डिजिटल सर्कुलेशन को रोकने का आदेश दिया। कोर्ट के दखल के बाद, NCERT ने क्लास 8 की किताब की फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह की कॉपियां वापस ले लीं और बिना शर्त माफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चैप्टर में न्यायपालिका से जुड़ी 'आपत्तिजनक' बातें थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने किताब पर नाराजगी जताई थी। क्लास 8 का चैप्टर हटाए जाने के कुछ महीनों बाद, NCERT की क्लास 9 की नई किताब में न्यायपालिका को एक 'निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था' के तौर पर दिखाया गया है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान को बनाए रखती है। 'पावर के बंटवारे' (separation of powers) के सिद्धांत को समझाया गया है और कहा गया है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप से काम करती है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) के तहत लाई गई 9वीं की नई बुक में लिखा, 'न्यायपालिका एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान की भावना को बनाए रखती है।' बुक में आगे लिखा है, 'न्यायपालिका कार्यपालिका के कामों और संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करती है, संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द कर सकती है और संविधान को बनाए रखती है।'

इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि न्यायपालिका लोकतांत्रिक मूल्यों और समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती है। सभी को न्याय मिल सके, यह पक्का करने के लिए न्यायपालिका समय-समय पर जनहित याचिकाओं (PILs) पर सुनवाई करती है। एनसीईआरटी का कहना है कि क्लास 9 की किताब NCF के तहत नए सिरे से तैयार किए गए करिकुलम का हिस्सा है, जिसमें संवैधानिक विषयों को अब एक ही किताब में समेटने के बजाय अलग-अलग क्लास में पढ़ाया जा रहा है। काउंसिल ने यह भी कहा है कि न्याय, आजादी, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे कॉन्सेप्ट अलग-अलग क्लास में धीरे-धीरे शामिल किए जाते हैं और वे सिलेबस का हिस्सा बने रहते हैं।

कानून और शासन से जुड़े विषयों को करीब से जानना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन अवसर

कॉलेज स्टूडेंट्स जो मानवाधिकार, कानून और शासन से जुड़े विषयों को करीब से जानना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन अवसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) दो हफ्ते का शॉर्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। जिसमें शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको मानवाधिकार के बारे में गहराई से समझने का अवसर देगा। साथ में आपको पैसे भी मिलेंगे। क्योंकि इंटर्नशिप पेड है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यह इंटर्नशिप वर्चुअल यानी ऑनलाइन होगी। इंटर्नशिप के दो हफ्तों में स्टूडेंट्स ह्यूमन राइट्स से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में समझेंगे। इसपर 40-45 सेशन होंगे। साथ में NHRC के अध्यक्ष- मेंबर्स की खास बातचीत, ह्यूमन राइट्स पर ग्रुप प्रोजेक्ट, बुक रिव्यू , पुलिस स्टेशन और एनजीओ की वर्चुअल फील्ड विजिट जैसी गतिविधियां भी करवाई जाएंगी। इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स की लिस्ट राष्ट्रीय मानवाधिकारिक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इंटर्नशिप या इससे जुड़ी अन्य किसी भी जानकारी के लिए स्टूडेंट्स फोन नंबर 011-24663371 और ईमेल आईडी internhsip.nhrc@gov.in पर सुबह 10 बजे से 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

एशिया कप 2027 की मेजबानी करेगा बांग्लादेश तारीखों का हुआ खुलासा

नेमार ने इंटरनेशनल फ़ुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया

ब्राज़ील का FIFA वर्ल्ड कप सफ़र राउंड ऑफ़ 16 में नॉर्वे से 2-1 की दिल तोड़ने वाली हार के साथ खत्म होने के बाद, नेमार ने इंटरनेशनल फ़ुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 34 साल के नेमार ने मैच खत्म होने की सीटी बजने के कुछ ही देर बाद अपने शानदार 16 साल के इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया और कहा कि 'सेलेकाओ' (ब्राज़ील टीम) के साथ उनका सफ़र अब खत्म हो गया है। यह ऐलान न्यू जर्सी में एक भावुक रात के बाद किया गया, जहाँ नेमार के स्टॉपेज-टाइम पेनल्टी गोल के बावजूद अर्लिंग हालैंड के देर से किए गए दो गोलों ने ब्राज़ील को चौंका दिया। हार के बाद बात करते हुए, भावुक नेमार ने माना कि उन्होंने एक आखिरी वर्ल्ड कप के लिए वापसी करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब उन्होंने मान लिया है कि उनका इंटरनेशनल करियर खत्म हो चुका है। नेमार ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब सब खत्म हो गया है।यह ऐलान न्यू जर्सी में एक भावुक रात के बाद किया गया, जहाँ नेमार के स्टॉपेज-टाइम पेनल्टी गोल के बावजूद अर्लिंग हालैंड के देर से किए गए दो गोलों ने ब्राज़ील को चौंका दिया। हार के बाद बात करते हुए, भावुक नेमार ने माना कि उन्होंने एक आखिरी वर्ल्ड कप के लिए वापसी करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब उन्होंने मान लिया है कि उनका इंटरनेशनल करियर खत्म हो चुका है। नेमार ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब सब खत्म हो गया है।ब्राज़ील के लिए उनका आखिरी गोल नॉर्वे के खिलाफ़ स्टॉपेज टाइम के आखिर में पेनल्टी स्पॉट से आया, लेकिन पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम के टूर्नामेंट से बाहर हो जाने के कारण यह गोल बस एक सांत्वना ही बनकर रह गया।

जिम्बाब्वे और एशियन गेम्स के लिए वीवीएस लक्ष्मण होंगे हेड कोच

भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेल रही है। अब तक दो मैच हो गए हैं और आज तीसरा मुकाबला ट्रेंट ब्रिज में होना है। पांच मैचों की ये सीरीज खत्म होने के बाद तीन वनडे मैच खेलेगी और इसके बाद भारतीय टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर जाएगी। इस सीरीज के दौरान टीम इंडिया की कोचिंग का काम वीवीएस लक्ष्मण देखेंगे। वे एशियन गेम्स के दौरान भी ये जिम्मेदारी उठाते हुए नजर आएंगे। टीम इंडिया इस वक्त लगातार मुकाबले खेल रही है। एक सीरीज के बाद दूसरी सीरीज शुरू हो जाती है। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 मैच खेलने के बाद इसी के खिलाफ तीन वनडे मैच भी खेलेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके बाद 23 जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा। यानी बीच में बहुत ज्यादा दिन का गैप नहीं है। यही वजह है कि इस सीरीज के लिए वीवीएस लक्ष्मण को बीसीसीआई ने हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। वीवीएस लक्ष्मण इस वक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई के हेड हैं और बीच बीच में टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी भी निभाते रहे हैं। खास बात ये भी है कि जिस वक्त एशियन गेम्स खेले जा रहे होंगे, उसी वक्त भारतीय टीम वेस्टइंडीज के भी खिलाफ सीरीज खेल रही होगी। यानी ये दोनों टूर्नामेंट करीब करीब साथ साथ हो रहे होंगे, इसलिए जहां एक ओर सीनियर टीम के साथ वेस्टइंडीज टूर पर गौतम गंभीर रहेंगे, वहीं एशियन गेम्स में वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के साथ जाएंगे। एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले टी20 फॉर्मेट यानी 20 ओवर के मैच होंगे। जिम्बाब्वे टूर पर केवल लक्ष्मण ही नहीं, पूर्व स्पिन गेंदबाज सुनील जोशी गेंदबाजी कोच की भूमिका में नजर आएंगे, वहीं ऋषिकेत कानितकर बैटिंग कोच का काम संभालेंगे।

एमबाप्पे ने मारिला की नस्लवादी टिप्पणियों कीकड़ी आलोचना की

फीफा विश्व कप में फ्रांस से हार के बाद पैराग्वे की राजनीति और फुटबॉल जगत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। फ्रांस के कप्तान किलियन एमबाप्पे ने पैराग्वे की सीनेटर सेलेस्टे अमारिला की नस्लवादी टिप्पणियों की सार्वजनिक रूप से कड़ी आलोचना की है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब अमारिला ने फ्रांस और पैराग्वे के बीच खेले गए प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले के बाद सामाजिक माध्यम पर एमबाप्पे को लेकर कई विवादित पोस्ट किए। बता दें कि शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। मैच का एकमात्र गोल किलियन एमबाप्पे ने पेनाल्टी के जरिए किया था। इसी हार के बाद पैराग्वे की लिबरल रेडिकल पार्टी से जुड़ी सीनेटर सेलेस्टे अमारिला ने एमबाप्पे की पृष्ठभूमि, रूप-रंग, शिक्षा और मूल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। मौजूद जानकारी के अनुसार, एमबाप्पे ने सोमवार को सामाजिक माध्यम एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि अमारिला की गैरजिम्मेदाराना और खुलेआम नस्लवादी टिप्पणियों ने पैराग्वे के खिलाड़ियों की ऐतिहासिक उपलब्धि को दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया है। उन्होंने लिखा कि उनके ऐसे व्यवहार के कारण अब लोग पैराग्वे की शानदार विश्व कप यात्रा को भूलकर केवल इस विवाद की चर्चा कर रहे हैं। एमबाप्पे ने अपनी प्रतिक्रिया में अमारिला को "घृणित महिला" बताते हुए कहा कि वह पैराग्वे की कांग्रेस में बैठने के योग्य नहीं हैं। उनके इस बयान के बाद मामला केवल फुटबॉल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नस्लवाद और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी को लेकर बहस शुरू हो गई।

भारतीय ने बताई वजह

ऑस्ट्रेलिया में प्लंबर बनना है ड्रीम जॉब

क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्लंबर 15 मिनट के काम के लिए 8 हजार रुपये से ज्यादा कमा सकता है? ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक भारतीय युवक का दावा है कि वहां प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और बढ़ई जैसे ट्रेड वर्कर्स को न सिर्फ अच्छी कमाई होती है, बल्कि समाज में उन्हें भरपूर सम्मान भी मिलता है. यही वजह है कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर एडी खनेजा नाम के भारतीय युवक ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि भारत में अक्सर बच्चों से कहा जाता है कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो प्लंबर या बढ़ई बन जाओगे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तस्वीर बिल्कुल अलग है. वहां कई बच्चे बड़े होकर

प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन या कारपेंटर बनने का सपना देखते हैं, क्योंकि इन पेशों में अच्छी कमाई और सम्मान दोनों मिलता है. वीडियो में एडी बताते हैं कि एक बार उनके घर का लॉक खराब हो गया था. उसे ठीक कराने के लिए उन्होंने एक कारपेंटर को बुलाया. कारपेंटर ने करीब 15 मिनट में काम पूरा किया और इसके लिए 150 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 8 हजार रुपये) फीस ली. उन्होंने कहा कि भारत में उनके घर के पास रहने वाले एक कारपेंटर की महीनेभर की कमाई शायद इससे भी कम होती होगी. इसी अनुभव के बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब तो लगता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, पहले कारपेंट्री सीखने के लिए कहूंगा.

माता-पिता के गर्व और खुशी के आंसू

एयर होस्टेस बेटी ने फ्लाइट में किया पेरेंट्स का वेलकम

कई सरप्राइज ऐसे होते हैं, जिन्हें इंसान जिंदगी भर नहीं भूल पाता. सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही कहानी लोगों का दिल जीत रही है. एक एयर होस्टेस ने अपने माता-पिता को ऐसा सरप्राइज दिया कि पहले तो वे हैरान रह गए और फिर उनकी आंखों में खुशी और गर्व साफ दिखाई देने लगा. दरअसल, सुष्मिता नाथ नाम की एक एयर होस्टेस ने अपने सोशल मीडिया एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह ऑन ड्यूटी अपने माता-पिता का वेलकम करते दिखाई दे रही है. यह वीडियो इसलिए भी वायरल हो रहा है, क्योंकि इसमें एयर होस्टेस के माता पिता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें यहां अपनी बेटी

मिल जाएगी. इसलिए इस वीडियो में माता- पिता का रिएक्शन देखने लायक है. सुष्मिता ने अपना माता- पिता से कहा था कि उस दिन उनकी ड्यूटी किसी दूसरी फ्लाइट में है. इसलिए उनके मम्मी-पापा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस विमान से वे सफर करने वाले हैं, उसी फ्लाइट में उनकी बेटी यात्रियों का स्वागत करेगी.

अमेरिका में परवल की लूट

अमेरिका के न्यूजर्सी में खुली एक भारतीय किराना दुकान के उद्घाटन पर पहले ही दिन इतनी भीड़ उमड़ी कि बाहर लंबी कतारें लग गईं और अंदर ग्राहकों से दुकान खचाखच भर गई. इस नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में किसी भारतीय किराना दुकान के खुलने पर भी वैसी ही भीड़ लग सकती है, जैसी भारत की सब्जी मंडियों में दिखती है? न्यू जर्सी में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक नए भारतीय ग्रॉसरी स्टोर के उद्घाटन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें थीं, जबकि अंदर खरीदारी के लिए लोगों से दुकान खचाखच भरी हुई थी. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में इसे 'अमेरिकन सब्जी मंडी' कहना शुरू कर दिया. किसी ने लिखा कि लग ही नहीं रहा कि यह अमेरिका है. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे भारत की किसी मंडी में खरीदारी चल रही हो. दरअसल, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए ऐसे स्टोर सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि अपने देश के स्वाद और यादों से जुड़ने का जरिया भी होते हैं.

क्यों बढ़ रही भारतीय स्टोर्स की लोकप्रियता?

भारतीय समुदाय के बढ़ने के साथ-साथ अमेरिका में भारतीय किराना स्टोर्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. इन दुकानों में लोगों को अपने देश का पसंदीदा खाना बनाने के लिए जरूरी सामान एक ही जगह मिल जाता है. यही कारण है कि नए स्टोर खुलने पर बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं. यह वीडियो सिर्फ भीड़ की वजह से वायरल नहीं हुआ, बल्कि इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसने विदेश में बसे भारतीयों के अपने खान-पान और संस्कृति से गहरे जुड़ाव को भी दिखाया है.

संस्कृत का बर्थडे गीत क्यों हो रहा वायरल?

क्या जन्मदिन की शुभकामना सिर्फ "हैप्पी बर्थडे टू यू" तक ही सीमित होनी चाहिए? या फिर ऐसी भी शुभकामना हो सकती है, जो इंसान के पूरे जीवन के लिए मंगलकामना करे? यही सवाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. लेखिका साहना सिंह ने संस्कृत में रचित 'जन्मदिनम इदम्' गीत का अर्थ समझाया. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई.

मूवी बैन होने पर दिलजीत बोले

घर-घर पहुंच गई 'सतलुज', अब नहीं रुकेगी

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' अब सोशल मीडिया पर चर्चा का हॉट टॉपिक बन गई है. 4 सालों तक CBFC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) के चक्कर में अटकी रही ये फिल्म शुक्रवार को अचानक ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हो गई थी, लेकिन रिलीज के 48 घंटों के अंदर ये फिल्म जी5 से भी हट गई.

अब दिलजीत ने अपनी फिल्म पर फिर से ब्रेक लगने पर रिएक्ट करते हुए एक इंस्टाग्राम लाइव किया है. बिना किसी चर्चा या प्रमोशन के अचानक रिलीज हुई 'सतलुज' की चर्चा आग की तरह फैली और जी5 से हटने से पहले लोगों ने खोजकर फिल्म खूब देखी. फिल्म रिलीज होने के बाद दिलजीत ने इंस्टाग्राम लाइव में

कहा था कि उन्हें ओटीटी से भी फिल्म के हट जाने का डर है, इसलिए दर्शकि चाहें तो इसे डाउनलोड करके रख लें. अब दिलजीत ने फिल्म के हटने पर फिर रिएक्ट करते हुए इंस्टाग्राम लाइव करते हुए कहा, 'जिस बात का मुझे शुक्रवार को ही अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, वो हो चुका है तो इसमें कोई शॉक की बात नहीं है.

'भाजपा के लिए धन ही धर्म'

अखिलेश यादव के आरोपों से गरमाई सियासत

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों, महंगाई और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर कंपनियों को लाभ पहुंचाने, भ्रष्टाचार बढ़ाने और जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने भारत और दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के दामों की तुलना करते हुए निशाना साधा है। अखिलेश ने लिखा- भाजपा की 'धर्म' और 'धन' दोनों राजनीति का अंत हो गया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट करते हुए बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख ने 'X' पर लिखा- भाजपा की 'धर्म' और 'धन' दोनों राजनीति का अंत हो गया है। दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम गिरने से पेट्रोल-डीजल के दामों में भारी कमी आई है। दूसरे देशों की पब्लिक को तेल के घटे दामों के रूप में लाभ मिला है, लेकिन इसके विपरीत भारत में भाजपा सरकार दाम नहीं घटा रही है। कंपनियों को लगातार फायदा पहुंचाने में लगी है। भाजपा सरकार कंपनियों की सगी है, जनता की नहीं। अखिलेश ने आगे लिखा- भारत में तेल या किसी भी चीज के दाम का अपना अनोखा 'भ्रष्ट अर्थशास्त्र' है। जो मांग-आपूर्ति से नहीं, बल्कि भाजपाई कमीशनखोरी से चलता है। जो कंपनियों के मुनाफे से जुड़ा है। सामान्य शब्दों में कहें तो कंपनियों का प्रॉफिट-लाभ जितनी ज्यादा होगा। भाजपा को कमीशन भी उतना ज्यादा मिलेगा। इसीलिए हमारे यहां हर चीज के दाम बढ़ने या कुल मिलाकर कहें कि महंगाई बढ़ने का कारण भाजपा की कमीशनखोरी है। जिसका खामियाजा आम जनता को महंगे तेल, परिवहन, यातायात, खाद्य पदार्थ व अन्य सभी सामान खरीद कर भुगतना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर भी बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश ने लिखा- जिन अनभिज्ञ, भोले-भाले समर्थकों को लगता था कि भाजपा ऐसा निकृष्ट कार्य नहीं कर सकती है। मंदिर-चोरी के बाद उनको भी समझ आ गया है कि भाजपाइयों के लिए 'धन' ही धर्म है। अब तो भाजपा और उनके संगी-साथियों को देखकर लोग दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। सपा मुखिया ने लिखा- भाजपा की धर्म की राजनीति का अंत हो गया है। इसीलिए वो अब केवल 'धन' की राजनीति करेगी। इससे भ्रष्टाचार भी बेतहाशा बढ़ेगा और महंगाई भी क्योंकि भाजपा के जिन करोड़ों वोटों में कमी आई है। उन वोटों की कमी को भाजपा पैसे से खरीद कर पूरा करना चाहेगी, लेकिन धर्म के नाम पर की गई चोरी के पैसों को कोई नहीं लेना चाहेगा।

कन्हैया माधवपुर में सीवर संकट गहराया, तीन साल से गंदे पानी में जीने को मजबूर लोग

कन्हैया माधवपुर वार्ड-31 में सीवर ओवरफ्लो और मुख्य सड़क पर सालभर भरा रहने वाला गंदा पानी सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण पिछले तीन सालों से घरों के सामने 12 महीने गंदा पानी जमा रहता है। वार्ड की सड़कों की हालत भी बदहाल है। जगह-जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करीब एक वर्ष पहले मेयर कोटे से बनी सड़क भी कई स्थानों पर उखड़ चुकी है और उसमें कई फीट लंबे गड्ढे बन गए हैं, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का जिम्मा एलएसए कंपनी के पास है, लेकिन लोगों का आरोप है कि कूड़ा समय पर नहीं उठाया जाता, जिससे कई स्थानों पर गंदगी फैली रहती है। लोगों का कहना है कि सड़क और सीवर नहीं होने की वजह से शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं। 3 साल से दुर्गंध झेल रहे लोग. तीन साल से अमन एनक्लेव कॉलोनी में लोगों के घरों के सामने गंदा पानी भरा रहता है। यहां पर पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण भी शुरू किया गया , लेकिन लेवलिंग सही नहीं होने के कारण यह काम अधूरे में छोड़ दिया गया। इसके बाद सीवर का काम देखने वाली स्वेज इंडिया के कर्मचारियों ने, जीएम जलकल सहित अन्य अधिकारियों ने कॉलोनी का दौरा किया। बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लोगों के घरों के आगे मानव मल तैर रहा है। फरीदीपुर, आसिफ नगर मुर्दापुर, विशाल सिटी और लाला बाग में सीवर की समस्या से लोग त्रस्त हैं। इन इलाकों में गंदे पानी की आपूर्ति भी होती है।

मोहम्मदाबाद गोहना सीट पर बसपा का बड़ा फैसला, जेके आजाद को मिला टिकट

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछने लगी है। बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने मऊ जिले की एकमात्र सुरक्षित विधानसभा सीट मोहम्मदाबाद गोहना से अपना पहला दांव चल दिया है। बसपा ने जेके आजाद को यहां से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि, इस ऐलान के साथ ही बसपा के अंदर स्थानीय कार्यकर्ताओं में विरोध के सुर उठने लगे हैं, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मोहम्मदाबाद गोहना सीट से टिकट मिलने के बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर जेके आजाद कौन हैं, जिन पर बसपा सुप्रीमो ने इतना बड़ा दांव खेला है। बसपा के युवा प्रत्याशी जेके आजाद मूल रूप से मऊ के पड़ोसी जिले आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उनका घर जहानागंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में है। बता दें वे एक गैर-राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने आजमगढ़ में बसपा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम किया है। इससे पहले आजाद ने जहानागंज नगर पंचायत चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमानी चाही थी लेकिन तब पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया था। बसपा के स्थानीय कार्यकर्ता जेके आजाद को बाहरी बताकर उनके नाम का कड़ा विरोध कर रहे हैं। समर्पित कार्यकर्ताओं का सवाल है कि जब जिले में ही पार्टी के पास कर्मठ नेताओं की भरमार है तो फिर बाहर से प्रत्याशी लाने की क्या जरूरत थी। उधर मऊ बसपा जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंटू ने इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताया है। उनका कहना है कि अगर कोई विरोध है तो उसे आपस में बैठकर सुलझा लिया जाएगा और सभी मिलकर बहन जी यानी मायावती को मजबूत करने का काम करेंगे।

एलडीए का बड़ा फैसला, 1700 अवैध भवन होंगे नियमित

एलडीए ने शहर के भीतर अवैध रूप से बने 1700 भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद एलडीए ने इन सभी भवन स्वामियों को नियमितीकरण के लिए नोटिस जारी किए हैं। ये सभी भवन ऐसे हैं, जिनके नक्शे पहले जिला पंचायत से पास हुए थे, लेकिन एलडीए सीमा में आने के बाद इन्हें तकनीकी रूप से अवैध माना जा रहा था। एलडीए ने कार्रवाई के लिए सभी स्वीकृत भवनों की जोनवार सूची तैयार की है। प्राधिकरण के नए प्लान के अनुसार, इस अभियान में सबसे पहले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी। इसके बाद आवासीय भवनों के नक्शे वैध किए जाएंगे। जिला पंचायत के नियमों के तहत बने मकानों और व्यावसायिक भवनों के मालिकों को एलडीए को भारी शमन शुल्क नहीं देना होगा। यदि निर्माण एलडीए के मास्टर प्लान के भूमि उपयोग के विपरीत है, तो उसे खारिज करने के बजाय समायोजित किया जाएगा। इसके लिए केवल निर्धारित अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इस फैसले से हजारों भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने कहा कि नियमावली के तहत कार्रवाई की जा रही है।

लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट

लखनऊ में बुधवार सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से आसमान में काले बादल छाए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। सुबह करीब 29 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले तीन घंटों में लखनऊ के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा के झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। इस दौरान गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की भी संभावना है। पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जबकि दोपहर 12 बजे के बाद बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है। सुबह से ही नमी का स्तर 83 फीसदी रहने के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। हालांकि 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने कुछ राहत जरूर दी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 81 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सपा का पलटवार, निशिकांत दुबे को भेजा कानूनी नोटिस

अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा गड़बड़ी मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अब कानूनी लड़ाई में बदलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी (सपा) ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। विवाद सोशल मीडिया पर किए गए उस दावे को लेकर है, जिसमें अयोध्या के चढ़ावा गड़बड़ी मामले के आरोपी टिन्नू यादव का नाम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जोड़ते हुए दावा किया गया था। सपा ने इसे पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए पोस्ट हटाने, सार्वजनिक माफी मांगने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। विवाद की शुरुआत भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। पोस्ट में दावा किया गया कि राम मंदिर में चढ़ावा गड़बड़ी मामले के आरोपी टिन्नू यादव ने पिछले ढाई वर्षों में अखिलेश यादव से 980 बार फोन पर बात की। इस दावे के बाद समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को निराधार बताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर निशिकांत दुबे को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों को समान संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने भगवान राम की मर्यादा, संसदीय परंपराओं और सामाजिक शिष्टाचार का हवाला देते हुए कहा कि निशिकांत दुबे अपनी 'झूठी पोस्ट' 10 मिनट के भीतर हटा लें, अन्यथा उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने इस कथित दावे को सोशल मीडिया पर साझा किया है, वे भी पोस्ट हटाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय से सद्बुद्धि पदयात्रा शुरू की

उन्नाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मंगलवार शाम जिला कांग्रेस कमेटी उन्नाव ने "सद्बुद्धि पदयात्रा" का आयोजन किया। इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने झंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक से हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति कर धन की लालसा पूरी करने वाले भाजपा नेताओं को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करें। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हनुमंत सिंह ने अपने संबोधन में पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कालनेमि राक्षस ने भेष बदलकर लोगों को भ्रमित किया था, उसी तरह आज विभिन्न स्वरूपों में समाज को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और जनता के बीच जाकर वास्तविक मुद्दों को उठाने का आह्वान किया। बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय से सद्बुद्धि पदयात्रा शुरू की। यह पदयात्रा कचहरी मार्ग से होते हुए पुल पार कर झंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। मंदिर में कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर देश में शांति, सौहार्द और सद्भाव बनाए रखने की प्रार्थना की। साथ ही, भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि देने की भी कामना की गई। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि कांग्रेस जनता के हितों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाज में भाईचारा, समानता और संविधान की भावना को मजबूत करना है। इस पदयात्रा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हनुमंत सिंह, उपाध्यक्ष संगठन चंद्र प्रकाश शुक्ला, डॉ. आर.एन. कुशवाहा, सतीश शुक्ला, विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अमरेंद्र प्रताप सिंह, फैज फारूकी, अजय गौतम, युसूफ फारूकी, सरफराज गांधी, सुनीत पाल, अशोक अवस्थी, पुत्तीलाल वर्मा, कमलेश तिवारी, तन्मय श्रीवास्तव, बाबूराम निषाद, सुरेश श्रीवास्तव, सलमान शाहिद, डॉ. शकील और संजय बाजपेयी सहित करीब आधा सैकड़ा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गंगा पुल के लिए, दो दिन के भीतर भवन खाली करने का निर्देश

उन्नाव के शुक्लागंज स्थित मिश्रा कॉलोनी में निर्माणाधीन नए गंगा पुल के लिए प्रशासन ने सात मकान मालिकों को दो दिन के भीतर भवन खाली करने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा के बाद भवनों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, ताकि पुल निर्माण कार्य में किसी तरह की बाधा न आए। नए गंगा पुल परियोजना की जद में कुल 38 मकान आ रहे हैं। इनमें से अधिकांश भवन स्वामियों को मुआवजे की राशि के चेक दिए जा चुके हैं। पिछले महीने से चल रहे अभियान के तहत अब तक 31 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि सात मकानों को अभी खाली कराया जाना बाकी है। नायब तहसीलदार धीरज त्रिपाठी ने प्रशासनिक टीम के साथ मिश्रा कॉलोनी पहुंचकर शेष भवन स्वामियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जिन मामलों में मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद है और प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, उनमें कोर्ट के आदेश के बाद ही मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण कार्य को समय पर पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रभावित मकान मालिक अरुण कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है, जबकि अन्य लोगों को भुगतान किया जा चुका है। उनका कहना है कि अधिकारियों ने यह कहकर चेक देने से इनकार कर दिया कि उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश सरकार की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने समीक्षा बैठक की

उन्नाव में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने मंगलवार दोपहर समीक्षा बैठक की। विकास भवन सभागार में आयोजित इस बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारी संगठनों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापार, उद्योग, बिजली, सड़क, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सहित व्यापारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना था। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने बताया कि यह जनपद में उद्योग एवं व्यापार से जुड़े लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद था। इसका लक्ष्य व्यापारियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और सुझावों को समझना था, ताकि उनके व्यापार और उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनाया जा सके। मंत्री ने जानकारी दी कि व्यापारियों ने कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित अपने सुझाव प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने इन सुझावों को गंभीरता से सुना और उनके समाधान पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकता है कि व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और वे आसानी से अपने कारोबार का विस्तार कर सकें। उद्योग विभाग के अधिकारियों पर व्यापारियों को परेशान करने और बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर पूछे गए सवालों पर प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों ने सकारात्मक ढंग से अपनी बात रखी और अधिकारियों ने भी उन्हें ध्यान से सुना। उनके अनुसार, कोई भी ऐसी गंभीर समस्या सामने नहीं आई जिसे तत्काल बड़े संकट के रूप में देखा जाए। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार व्यापार को मजबूत करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही उद्यमियों के लिए बेहतर कारोबारी माहौल बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही हैं। बैठक के समापन पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए।

किसान की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

उन्नाव में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक किसान की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पहले अज्ञात के रूप में जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। मंगलवार सुबह परिजनों ने शव की पहचान की, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। मृतक की पहचान अचलगंज थाना क्षेत्र के कोरारी कला गांव निवासी 65 वर्षीय बसंत लाल गौतम के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, वह खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। बताया गया कि सोमवार शाम करीब 6:30 बजे बसंत लाल बाजार जाने की बात कहकर घर से निकले थे। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान पुलिस को कोरारी-कोटारिया के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति के ट्रेन की चपेट में आने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन तत्काल पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में अज्ञात के रूप में रखवा दिया गया। मंगलवार सुबह परिजनों ने मोर्चरी पहुंचकर शव की पहचान बसंत लाल गौतम के रूप में की, जिससे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, बसंत लाल गौतम की मौत ऊंचाहार एक्सप्रेस की चपेट में आने से हुई है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हादसा रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ या किसी अन्य कारण से। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उन्नाव में झमाझम बारिश से मिली गर्मी से राहत, मौसम हुआ सुहावना

उन्नाव में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को मौसम ने राहत दी। सुबह से आसमान में बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। करीब नौ बजे शुरू हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। आसीवन, सफीपुर, गंजमुरादाबाद, बांगरमऊ, शुक्लागंज और उन्नाव शहर समेत जिले के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मौसम बदलने के बाद काफी राहत मिली। हालांकि, कुछ स्थानों पर बारिश के कारण जलभराव और कीचड़ की समस्या भी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में कमी आने से गर्मी और उमस का असर कम हो गया और मौसम सुहावना हो गया। लगातार गर्मी के कारण खेतों की नमी कम हो रही थी और किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। मंगलवार की बारिश को किसानों ने खरीफ फसलों के लिए लाभकारी बताया। उनका कहना है कि इससे खेतों में पर्याप्त नमी आएगी और धान की नर्सरी समेत अन्य फसलों की तैयारी में मदद मिलेगी। किसान रामलाल और हरिप्रसाद ने बताया कि लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण सिंचाई पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा था। अब बारिश से खेतों को फायदा मिलेगा और फसलों की बढ़वार बेहतर होने की उम्मीद है।

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के पूर्व महासचिव चंपत राय ने चुप्पी तोड़ी

चंपत राय ने अपने पत्र में आगे लिखा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दान पेटी की गिनती के दौरान कथित चोरी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई लोगों ने मुझ पर निराधार व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं अब तक चुप रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि SIT की अंतिम रिपोर्ट के बाद, मैं उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दूंगा और पूरी सच्चाई सामने आएगी।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी (Ayodhya Ram Mandir Donation Theft) मामले पर 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के पूर्व महासचिव चंपत राय ने चुप्पी तोड़ी है। चंपत राय ने रामभक्तों के नाम पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि 2024 से दानपात्र की गणना के दौरान कथित चोरी को लेकर मेरे खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन मैंने जानबूझकर मौन बनाए रखा। सोमवार को ट्रस्ट की बैठक में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की गई थी, जो अब सार्वजनिक हो चुकी है। रिपोर्ट पहले गोपनीय थी, इसलिए मैंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। SIT की अंतिम जांच पूरी होने के बाद ही मैं अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों और दुष्प्रचार का तथ्यात्मक जवाब दूंगा। अंतिम जांच के बाद सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के पूर्व महासचिव चंपत राय ने अपने पत्र में लिखा कि उन्हें साल- 1991 में संगठन की ओर से अयोध्या भेजा गया था। चंपत राय ने कहा कि उनका करीब 45 सालों का सार्वजनिक जीवन खुली किताब की तरह है और उन्हें विश्वास है कि अंततः सत्य की ही जीत होगी। चंपत राय ने अंत में लिखा कि वह सत्य का सम्मान करते हैं और अंतिम जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे। चंपत राय ने अपने पत्र में आगे लिखा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दान पेटी की गिनती के दौरान कथित चोरी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई लोगों ने मुझ पर निराधार व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं अब तक चुप रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि SIT की अंतिम रिपोर्ट के बाद, मैं उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दूंगा और पूरी सच्चाई सामने आएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मंगलवार को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने अपनी बात रखी। गोविंद देव गिरि ने कह कि मैं जब ये कहता हूं कि वे (चंपत राय) निर्दोष हैं, तो मेरा मतलब है कि इस पूरे कांड के साथ उनका कोई चारित्रिक संबंध नहीं हो सकता। उन्होंने एक अपराधी को अपना ड्राइवर रखा था। ड्राइवर के पास चाबियां थीं, सब कुछ वही कंट्रोल करता था। चंपत राय के ड्राइवर ने ही यह सब किया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा- मुझे आशंका है कि ड्राइवर बाहरी लोगों से जुड़ा था। यह सब CEO नहीं होने की वजह से हुआ। इसलिए हम एक CEO लाएंगे। दूसरी ओर, ट्रस्ट के नए महासचिव कृष्ण मोहन दास ने आज कामकाज संभाल लिया है।

राम मंदिर में दान चोरी के मामले को लेकरडॉ. एसटी हसन नेतीखी प्रतिक्रिया दी

अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान चोरी के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस मंदिर को करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है, वहां इस तरह की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और जांच पूरी निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। डॉ. एसटी हसन ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। उनका कहना था कि जो लोग मंदिर की दान राशि लेकर फरार हुए, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई केवल छोटे लोगों तक सीमित दिखाई दे रही है, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों पर अब तक कोई सख्त कदम नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि छोटी मछलियों को पकड़ा जा सकता है तो बड़े मगरमच्छों को क्यों छोड़ा जा रहा है। पूर्व सांसद ने कहा कि यदि वास्तव में भगवान श्रीराम के प्रति आस्था और श्रद्धा है तो उनके मंदिर के भीतर हुई इस कथित नापाक हरकत के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके खिलाफ भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि आस्था के नाम पर राजनीति करने वालों को अब इस मामले में अपनी प्रतिबद्धता साबित करनी चाहिए।

बनारस रेलवे स्टेशन पर सीलिंग फैन से टपकने लगा पानी

यूपी के वाराणसी जिले में बनारस रेलवे स्टेशन का एक वीडियो काफी चर्चा में है। यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 8 पर बारिश में पानी गिरते हुए देखा जा सकता है। वहीं वीडियो को लेकर सवाल उठाए जाने पर रेलवे ने एक बयान जारी कर सफाई दी है। रेलवे का कहना है कि जल निकासी अस्थायी रूप से बाधित हुई थी, जिसे ठीक कर लिया गया है। दरअसल, वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बनारस रेलवे स्टेशन पर सीलिंग से पानी की लीकेज हो रही है। यह पानी पंखों के जरिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गिरता हुए देखा जा सकता है। यह मामला बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 8 का बताया जा रहा है। वीडियो में एक शख्स कहता है 'बरसात में ये हाल है, पहली बरसात में ही इसका ये हाल हो गया। अब लोग कहां बैठेंगे। यहां से लेकर वहां तक हर जगह दरार ही दरार हो गई है। इसे दुरुस्त कीजिए, इसका उद्घाटन पीएम मोदी किए थे, क्यों बेज्जती करा रहे हो।' सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है। हालांकि इस घटना को लेकर रेलवे ने अब एक बयान जारी किया है। रेलवे ने एक बयान में कहा, "बनारस स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 8 पर स्थित PP शेल्टर के ऊपर बने वैली गटर की भारी वर्षा के दौरान डाउन पाइप एवं वैली गटर के जोड़ पर तेज हवा से जमा पत्तियों व पतंग के कारण जल निकासी अस्थायी रूप से बाधित हुई। सूचना मिलते ही तत्काल सफाई कर जल निकासी सुचारू कर समस्या का समाधान किया गया।"

ताज महल को लेकर एक बार फिर अदालत में बहस तेज हो गई

ताज महल को लेकर एक बार फिर अदालत में बहस तेज हो गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर याचिका ने उस पुराने विवाद को फिर जगा दिया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ताज महल दरअसल प्राचीन शिव मंदिर "तेजो महालय" है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सर्वे से इतनी परेशानी क्यों है? यदि दावे गलत हैं तो वैज्ञानिक और ऐतिहासिक जांच से डर किस बात का है, और यदि दावे सही नहीं ठहरते तो अदालत के सामने सच अपने आप आ जाएगा। फिर सर्वे कराने में हिचकिचाहट क्यों दिखाई जा रही है? दरअसल मामला वर्ष 2015 में आगरा की दीवानी अदालत में दायर उस वाद से जुड़ा है जिसमें दावा किया गया कि ताजमहल मूल रूप से भगवान शिव का मंदिर था। याचिकाकर्ताओं में भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान, अधिवक्ता हरिशंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री समेत अन्य लोग शामिल हैं। उनका कहना है कि यह संरचना मुगल काल से पहले की है और इसे राजा परमर्दि देव ने वर्ष 1212 में बनवाया था। बाद में यह राजा मानसिंह और फिर जयसिंह के अधिकार में रही, जिसके बाद शाहजहां ने इसे अपने कब्जे में लेकर मुमताज महल के मकबरे में बदल दिया। याचिका में यह भी कहा गया कि ताज महल परिसर के कई हिस्से आज भी आम जनता के लिए बंद हैं और उन्हीं हिस्सों की जांच सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2019 में अदालत से मांग की गई थी कि एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर ताजमहल का सर्वे कराया जाए, उसकी तस्वीरें ली जाएं और वीडियोग्रफी कराई जाए ताकि संरचना के वास्तविक स्वरूप की जांच हो सके।